यूपी-जापान साझेदारी को नई गति: ₹600 करोड़ के यामानाशी फंड और 'जापान डेस्क' का ऐलान

यामानाशी फंड से यूपी के MSMEs को मिलेगा बल, चार MoU से भारत-जापान साझेदारी को नई गति

लखनऊ, 21 अगस्त: उत्तर प्रदेश और जापान ने शुक्रवार को कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, पर्यटन और जापानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) से जुड़े चार समझौता ज्ञापनों (MoUs) के साथ अपनी साझेदारी को नई गति दी। इसके अलावा, यामानाशी ने उत्तर प्रदेश के एमएसएमई (MSME) क्षेत्र को सहयोग देने के लिए **₹600 करोड़ के फंड** की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी निवेश को बढ़ावा देने के लिए **Invest UP में समर्पित यामानाशी डेस्क** स्थापित करने तथा **JETRO और JICA के साथ नियमित समन्वय** की भी घोषणा की।

ये घोषणाएं लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित **जापान–भारत बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट** में की गईं। कार्यक्रम में यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी, जापानी उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों तथा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया।

₹600 करोड़ का यामानाशी फंड और समर्पित डेस्क से मजबूत होगी यूपी-जापान निवेश साझेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान के साथ साझेदारी को केवल निवेश चर्चाओं तक सीमित न रखकर इसे **संरचित और दीर्घकालिक सहयोग** में बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ₹600 करोड़ का यामानाशी फंड उत्तर प्रदेश के MSMEs को सहयोग देगा, जबकि Invest UP में स्थापित होने वाला समर्पित यामानाशी डेस्क जापान के इस प्रीफेक्चर के निवेशकों और कारोबारियों के लिए एक केंद्रित संपर्क माध्यम के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि JETRO और JICA के साथ नियमित समन्वय से निवेश के नए अवसरों की पहचान, निवेशकों की समस्याओं के समाधान और परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक ढांचे, कुशल मानव संसाधन और निवेश-अनुकूल नीतियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य ऐसी साझेदारी विकसित करना चाहता है, जिसमें **निवेश, तकनीक, कौशल और रोजगार एक साथ आगे बढ़ें।**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जापान केवल उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण निवेश साझेदार ही नहीं, बल्कि हमारी विकास यात्रा का दीर्घकालिक सहयोगी है। हम इस संबंध को अधिक संरचित और परिणामोन्मुख बनाना चाहते हैं। ₹600 करोड़ का यामानाशी फंड, Invest UP में समर्पित यामानाशी डेस्क तथा JETRO और JICA के साथ नियमित समन्वय हमें संवाद से क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के पास वह व्यापक बाजार, बुनियादी ढांचा और युवा कार्यबल है, जिसकी जापानी कंपनियों को आवश्यकता है, जबकि जापान के पास ऐसी तकनीक, कौशल और

वैश्विक अनुभव है, जो हमारी विकास गति को तेज कर सकता है। हमारा उद्देश्य ऐसी साझेदारी बनाना है, जो निवेश, रोजगार और दीर्घकालिक संस्थागत संबंधों को बढ़ावा दे।"

उन्होंने कहा कि यह सहयोग उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख निवेश और विनिर्माण गंतव्य बनाने तथा **1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** के लक्ष्य को हासिल करने की राज्य की व्यापक में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

चार MoU से कौशल, पर्यटन, GCC और रोजगार सहयोग को मिला विस्तार

कार्यक्रम में चार MoU का आदान-प्रदान हुआ। पहला MoU **Invest UP और Technical Training & Research Centre, Kanpur** के बीच तकनीकी प्रशिक्षण और कार्यबल विकास को लेकर हुआ। Japan Technical Training Centre के निदेशक **शुइची कामादा** को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जापान में रोजगार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के तीन प्रशिक्षुओं को भी सम्मानित किया गया।

दूसरा MoU **पर्यटन विभाग और यामानाशी प्रीफेक्चर** के प्रतिनिधियों के बीच हुआ। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि और पर्यटन संबंधों को मजबूत करना है। इसके माध्यम से जापानी पर्यटकों के बीच उत्तर प्रदेश के बौद्ध, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

तीसरा MoU **Invest UP और यामानाशी प्रीफेक्चर** के प्रतिनिधियों के बीच हुआ। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में **जापानी Global Capability Centres (GCCs)** की स्थापना को बढ़ावा देना है। इससे तकनीक, डिजिटल सेवाओं, बिजनेस ऑपरेशंस और उच्च-कुशल रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

चौथा MoU **श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और यामानाशी प्रीफेक्चर** के प्रतिनिधियों के बीच हुआ। इसका फोकस **जापानी भाषा में दक्ष कार्यबल की निरंतर उपलब्धता** सुनिश्चित करना है। इससे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण और जापान में रोजगार की जरूरतों के बीच एक व्यवस्थित संपर्क स्थापित होगा।

इन समझौतों से जापानी निवेश को कौशल विकास, रोजगार, पर्यटन और तकनीकी सहयोग के साथ जोड़ने का व्यापक ढांचा तैयार हुआ है।

हेल्थकेयर, फूड प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी में सहयोग के नए अवसर

UP–Japan Healthcare and Care Economy Partnership सत्र में उपमुख्यमंत्री **श्री ब्रजेश पाठक** ने कहा कि उत्तर प्रदेश जापान की जरूरतों के अनुरूप अपने मेडिकल और पैरामेडिकल प्रशिक्षण तंत्र को तैयार करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 47 से बढ़कर 83 से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और जापानी भाषा कौशल के माध्यम से युवाओं को जापान में स्वास्थ्य क्षेत्र के अवसरों के लिए तैयार किया जा सकता है।

कौशल विकास मंत्री **श्री कपिल देव अग्रवाल** ने कहा कि जापान की तकनीकी क्षमता और उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति मिलकर स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सहयोग का नया मॉडल तैयार कर सकती है। उन्होंने जापानी कंपनियों से तकनीक, विशेषज्ञता और निवेश के साथ उत्तर प्रदेश आने का आह्वान किया।

श्रम मंत्री **श्री अनिल राजभर** ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को भारत और विदेश दोनों जगह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। जापान के साथ साझेदारी युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार का एक व्यवस्थित मार्ग तैयार कर सकती है।

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य **अमित घोष** ने जापानी हेल्थकेयर तकनीक, रोबोटिक्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की संभावनाएं बताईं। उन्होंने प्रस्तावित **400 एकड़ के MedTech Park** और PPP मॉडल पर बनने वाले मेडिकल कॉलेजों को जापानी निवेश और तकनीक हस्तांतरण के लिए संभावित क्षेत्र बताया।

खाद्य प्रसंस्करण सत्र में उपमुख्यमंत्री **श्री केशव प्रसाद मौर्य** ने कहा कि उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता, जल संसाधन और युवा कार्यबल राज्य को वैश्विक फूड प्रोसेसिंग हब बनाने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने कहा कि जापानी तकनीक और सप्लाई चेन विशेषज्ञता से कृषि उत्पादों को उच्च मूल्य वाले प्रसंस्कृत उत्पादों में बदलकर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है।

भारत में जापान के राजदूत **ओनो केइची** ने तकनीक, निवेश और कौशल को स्थानीय अवसरों से जोड़ने वाली व्यावहारिक साझेदारियों पर जोर दिया। Kikkoman India के निदेशक **हैरी हाकुई कोसाटो** ने स्थानीय विनिर्माण, खाद्य उद्योग, उपभोक्ता बाजार और निर्यात में अवसरों को रेखांकित किया।

ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी सहयोग आगे बढ़ा। **UPNEDA और जापानी प्रतिनिधिमंडल के बीच MoU** का आदान-प्रदान हुआ, जिसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा वैल्यू चेन और तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है। IIT Kanpur और IIT BHU में स्थापित Centres of Excellence को शोध, प्रतिभा विकास और तकनीक हस्तांतरण के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में रेखांकित किया गया।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री **श्री जयवीर सिंह** ने कहा कि उत्तर प्रदेश बौद्ध स्थलों पर कनेक्टिविटी, पर्यटक सुविधाओं, आवास और बेहतर अनुभव विकसित करने पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों के कारण जापान उत्तर प्रदेश के लिए स्वाभाविक पर्यटन साझेदार है।

उन्होंने कहा कि **यामानाशी को जापान में उत्तर प्रदेश पर्यटन के महत्वपूर्ण गेटवे के रूप में विकसित करने** का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म, आध्यात्मिकता, वेलनेस और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले जापानी पर्यटकों के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कौशांबी और संकिसा को प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में रेखांकित किया गया।

यामानाशी के साथ संस्थागत संबंधों को भी मिली नई मजबूती

औद्योगिक विकास मंत्री **श्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी'** ने कहा कि जापानी कंपनियों की अधिक भागीदारी से उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और निवेश क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्होंने जापानी निवेशकों के लिए बेहतर सुविधा तंत्र और मजबूत संपर्क व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष **श्री सतीश महाना** ने यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस दौरान **यामानाशी प्रीफेक्चरल असेंबली और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बीच फ्रेंडली एक्सचेंज एमओयू** पर हस्ताक्षर हुए। MoU पर श्री सतीश महाना और यामानाशी विधानसभा के चेयरमैन **हिदेनोरी मियामोतो** ने हस्ताक्षर किए। बातचीत में काशी और बौद्ध सर्किट को दोनों क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कड़ी के रूप में रेखांकित किया गया।

नए समझौतों और पहलों से उत्तर प्रदेश-जापान संबंधों को एक व्यापक संस्थागत आधार मिला है, जिसमें **MSME वित्तीय सहयोग, निवेश सुविधा, कौशल, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, हरित ऊर्जा और तकनीक** शामिल हैं। ₹600 करोड़ के यामानाशी फंड, समर्पित यामानाशी डेस्क और JETRO-JICA के साथ नियमित समन्वय के माध्यम से उत्तर प्रदेश जापानी निवेश को अधिक तेज, व्यवस्थित और परियोजना-केंद्रित बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

यह साझेदारी उत्तर प्रदेश की व्यापक विकास रणनीति से जुड़ती है, जिसमें मजबूत बुनियादी ढांचे, विशाल बाजार और युवा प्रतिभा के आधार पर वैश्विक निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार, तकनीक और सतत आर्थिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां मजबूत की जा रही हैं।
